वारदात | शहपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम मंगेला सूरजपुरा का मामला

घर में मिली महिला की लाश, गांव में हड़कंप

शहपुरा नवभारत 4 नवंबर। शहपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम मंगेला सूरजपुरा में उस समय सनसनी फैल गई जब गांव की महिला सोनवती परस्ते का शव घर के अंदर संदिग्ध अवस्था में मिला। महिला का शव की सूचना पाकर ग्रामीणों में हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई।

घटना की जानकारी मिलते ही शहपुरा पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा कार्यवाही कर शव को अपने कब्जे में लिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शहपुरा भेजा, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और घटना के कारणों का पता लगाने में जुटी है।

ग्राम गुतली रैयत गांव स्थित खेत में मिली वृद्ध की खून से सनी लाश

शहपुरा नवभारत 4 नवंबर। शहपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम गुतली रैयत में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब खेत में एक वृद्ध की खून से लथपथ लाश पाई गई। मृतक की पहचान विष्णु उरैती (उम्र 56 वर्ष) निवासी गुतली रैयत के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वृद्ध विष्णु अपने खेत में बनी झोपड़ी में रहकर फसल की रखवाली करता था। मंगलवार शाम लगभग 5 बजे ग्रामीणों ने शव को देखकर पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही शहपुरा थाना पुलिस, एफएसएल टीम और बालाघाट से डॉग स्क्वायड टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। फिलहाल पुलिस ने मौके का पंचनामा तैयार कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, वहीं घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच जारी है। गांव में इस घटना के बाद दहशत का माहौल बना हुआ है।

अब तक नहीं हुआ किसानों की फसलों का सर्वे

▶ कलेक्टर के आदेश के बाद भी विभागीय अमला नदारद

शहपुरा नवभारत 4 नवंबर। बेमौसम बारिश और तेज हवाओं के कारण किसानों की फसलें पूरी तरह बर्बाद हो चुकी हैं। लगातार हो रही वर्षा से धान की फसलें खेतों में गिर गई हैं, जिससे इल्ली और हल्दीगाठी रोग का प्रकोप भी बढ़ रहा है।

बढ़ती शिकायतों को देखते हुए जिला कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया ने संबंधित विभागों को किसानों के खेतों में जाकर सर्वे करने के निर्देश जारी किए थे, लेकिन कलेक्टर के आदेश के बावजूद अब तक कोई भी विभागीय अमला गांवों तक नहीं पहुंचा है। किसानों का कहना है कि बारिश और आंधी-तूफान ने उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया है। फसलें सड़ने लगी हैं, लेकिन न तो कोई अधिकारी हाल-चाल जानने आया और न ही नुकसान का सर्वे किया गया।

किसानों ने प्रशासन पर लगाया लापरवाही का आरोप

किसानों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि विभागीय अधिकारी किसानों की समस्याओं से बेपरवाह बने हुए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि फसलों की हालत दिन-ब-दिन बिगड़ती जा रही है, और यदि समय पर सर्वे नहीं किया गया तो नुकसान का आकलन करना मुश्किल हो जाएगा। किसानों ने शासन-प्रशासन से तत्काल सर्वे कर राहत राशि प्रदान करने की मांग की है।

▶ एक नजर में ◀

बस सुविधा को लेकर विद्यार्थियों ने सौंपा ज्ञापन

उमरिया 4 नवंबर। जिले के प्रमुख महाविद्यालयों में बस परिवहन सुविधा बंद होने से छात्र-छात्राओं में भारी आक्रोश व्याप्त है। इसी मुद्दे को लेकर मंगलवार को भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के नेतृत्व में सैकड़ों छात्र-छात्राओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। छात्रों की मुख्य मांग है कि आदर्श महाविद्यालय उमरिया एवं प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस (शा. रणविजय प्रताप सिंह महाविद्यालय) में तत्काल बस परिवहन सुविधा पुन: शुरू की जाए। छात्रों का कहना है कि आदर्श महाविद्यालय जिला मुख्यालय से लगभग 6-7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और कॉलेज तक पहुंचने का रास्ता घने जंगलों से होकर गुजरता है, जिससे छात्राओं की सुरक्षा को लेकर हमेशा खतरा बना रहता है। परिवहन सुविधा के अभाव में छात्र-छात्राओं को ऑटो या निजी साधनों का सहारा लेना पड़ता है, जिससे आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। इस अवसर पर संगठन के जिला अध्यक्ष मो. असलम शेर के नेतृत्व में हुए इस ज्ञापन कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी जिला उपाध्यक्ष पुष्पराज सिंह, उपाध्यक्ष कृष्ण कांत तिवारी, ब्लॉक अध्यक्ष अम्बर शुक्ला, आदर्श कॉलेज अध्यक्ष अजय असाटी ओम, शीतला प्रताप सिंह कॉलेज अध्यक्ष अनुराग तिवारी, रणविजय प्रताप सिंह महाविद्यालय अध्यक्ष ओम तिवारी, ब्लॉक उपाध्यक्ष कृष्ण कुमार रजक, जिला महासचिव शुभम महोबिया, कॉलेज सचिव सचिन चौधरी , कॉलेज सचिव राजा रावत आदि भारी संख्या में पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं मौजूद रहीं।

घर-घर जाकर होगा मतदाता सूची का सत्यापन

डिंडोरी, नवभारत 4 नवंबर। निर्वाचन आयोग भारत सरकार द्वारा राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया प्रारम्भ की जा रही है। इसके अंतर्गत 4 नवम्बर से 4 दिसम्बर तक सभी विधानसभा क्षेत्रों में घर-घर जाकर मतदाता सूची का सत्यापन किया जाएगा। इस अवधि में प्रत्येक बूथ लेवल अधिकारी मतदाताओं के निवास पर जाकर उनके नाम, पता, आयु एवं अन्य विवरणों का भौतिक सत्यापन करेंगे। निर्वाचन आयोग ने सभी नागरिकों से इस प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी एवं पूर्ण सहयोग का आग्रह किया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश संजीव झा ने नागरिकों से अपील की है कि जब बीएलओ उनके घर पहुंचें, तो आवश्यक सहयोग प्रदान करें।

बीएलओ किसी प्रकार के दस्तावेज़ एकत्र नहीं करेंगे-उल्लेखनीय है कि घर-घर सर्वेक्षण के दौरान बीएलओ किसी प्रकार के दस्तावेज़ एकत्र नहीं करेंगे। दस्तावेज़ केवल तभी आवश्यक होंगे जब किसी प्रविष्टि का सत्यापन पूर्ववर्ती रिकॉर्ड से मेल न खाए। ऐसी स्थिति में संबंधित निर्वाचन रजिस्ट्री अधिकारी (श्वत्रह्र) अलग से सूचना देकर आवश्यक दस्तावेज़ मांगेगा। बीएलओ आयोग द्वारा अधिकृत पहचान-पत्र लेकर आएंगे, अत: नागरिक उनसे पहचान-पत्र देखकर ही जानकारी साझा करें।

दावा या आपत्ति दर्ज करा सकेंगे-घर-घर सत्यापन के उपरांत 9 दिसम्बर 2025 को प्रारूप (ष्ठह्म्ड्डद्घह्ल) मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। नागरिक 9 दिसम्बर से 8 जनवरी 2026 तक अपने नाम संबंधी दावा या आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 7 फरवरी 2026 को किया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने सभी नागरिकों से अपील की है कि घर-घर मतदाता सत्यापन अभियान में सक्रिय सहयोग प्रदान करें, ताकि मतदाता सूची की शुद्धता, पारदर्शिता और समावेशिता सुनिश्चित हो सके।

रिटायर्ड शिक्षक सम्पत कुमार का निधन

चिल्हारी। जिले के चिल्हारी निवासी रिटायर्ड शिक्षक सम्पत कुमार द्विवेदी का मंगलवार को दुखद निधन हो गया। श्री द्विवेदी विगत कुछ दिनों से सर्दी खांसी बुखार से पीड़ित थे, जिनका ईलाज कटनी में कराया जा रहा था। श्री द्विवेदी पूर्व जिला पंचायत सदस्य अनिल कुमार द्विवेदी के पिता हैं।

पनपथा बफर के पिटौर से हटाया अतिक्रमण

चिल्हारी नवभारत 4 नवंबर। उप वनमंडलाधिकारी पनपथा ने बताया कि वन परिक्षेत्र पनपथा बफर की बीट पिटौर के कक्ष क्रमांक पी एफ-623 में आरोपी दशरथ साहू द्वारा ट्रैक्टर से जुताई की जाने की सूचना प्राप्त होने पर गठित टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर अतिक्रमण के प्रयास को विफल करते हुए 2.5 हेक्टेयर वन भूमि अतिक्रमण से मुक्त कराकर ट्रैक्टर को जब्त कर आरोपी को हिरासत में लिया गया है।

उन्होंने बताया कि प्रकरण में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। जप्त ट्रैक्टर की अनुमानित कीमत चार लाख रूपये है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की कार्यवाही सतत रूप से जारी रहेगी। कार्यवाही के दौरान परिक्षेत्र अधिकारी पनपथा बफर एवं कोर तथा स्टाफ उपस्थित रहा।

एक सीईओ को तीन जनपद का प्रभार, आम जनता परेशान

▶ डिंडौरी, शहपुरा और मेहंदवानी के विकास कार्य ठप

शहपुरा नवभारत। जनपद पंचायतों में विकास कार्यों पर सीधा असर पड़ रहा है। दरअसल, जनपद पंचायत मेहंदवानी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) को अतिरिक्त रूप से डिंडौरी और शहपुरा जनपद पंचायतों का प्रभार भी सौंपा गया है। एक ही अधिकारी के पास तीन जनपदों की जिम्मेदारी होने से प्रशासनिक कार्य और सरकारी योजनाएं प्रभावित हो रही हैं।

ग्रामीणों, सरपंचों और सचिवों को अपने पंचायत संबंधी कार्यों के लिए जनपद कार्यालय के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, लेकिन सीईओ की अनुपस्थिति के कारण उन्हें निराश होकर लौटना पड़ता है। शहपुरा जनपद पंचायत में तो हालात और भी गंभीर हैं। यहां कई महत्वपूर्ण फाइलें और प्रस्ताव लंबित पड़े हैं। आरटीआई से संबंधित कार्यवाही, पंचायत योजनाओं की स्वीकृति और निर्माण प्रस्तावों की फाइलें महीनों से 'पेंडिंग' बताई जा रही हैं।

सीईओ के केबिन में लटका मिलता है ताला

जनपद पहुंचने वाले लोगों का कहना है कि जब वे किसी काम या शिकायत को लेकर सीईओ से मिलने आते हैं, तो उनके केबिन में ताला लटका हुआ मिलता है। स्थानीय लोगों ने व्यंग्य में कहा कि 'अब तक नए जनपद सीईओ शहपुरा के दर्शन तक नहीं हो सके।'

जनपद सदस्य ने लिखा प्रभारी मंत्री को पत्र

इस पूरे मामले को लेकर जनपद सदस्य संतोष सिंह चंदेल (क्षेत्र क्रमांक 17, डिंडौरी) ने जिला प्रभारी मंत्री प्रतिमा बागरी को पत्र लिखकर मांग की है कि डिंडौरी जनपद पंचायत के लिए स्थायी सीईओ की नियुक्ति की जाए, ताकि जनहित के कार्य समय पर हो सकें। चंदेल ने कहा कि 'एक ही अधिकारी के पास तीन जनपदों का कार्यभार होना शासन की योजनाओं की गति को रोक रहा है। पंचायत स्तर पर विकास कार्य लगभग ठप्प पड़ चुके हैं।

लाड़ली बहना सर्वे के नाम पर पंचायतों में की जा रही उगाही

▶ मकान नंबर प्लेट को लेकर गड़बड़ी की आशंका, सीईओ का पत्र दिखाकर लोगों को कर रहे भ्रमित

नवभारत उमरिया 4 नवंबर। पाली जनपद के बाद अब करकेली में मकान नंबर प्लेट लगाने के नाम पर हितग्राहियों से 50 रुपए लिये जाने पर विवाद शुरू हो गया है।

धवइझर गांव में पंचायत की मदद से 20-25 मकानों में यह प्लेट लगाकर प्रति लाड़ली बहना हितग्राही से इस शुल्क की वसूली की गई है। मामला तूल पकड़ने पर ये लोग सीईओ का एक पत्र दिखाकर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। पत्र में दावा किया गया है कि इस नंबर प्लेट से हितग्राही को शासकीय योजना का लाभमिलने में सुविधा होगी। दूसरी तरफ कांग्रेस नेता इसे जनता के अधिकारों पर कुठाराघात करार दे रहे हैं। एक से अधिक पहचान पत्र के बाद भी शुल्क लेकर नंबर प्लेट लगाना विधि विरुद्ध कहा जा रहा है।

बिहार का गिरोह जिले में घूम रहा

बताया जा रहा है कि नंबर प्लेट लगाने के लिए बिहार के कुछ लोगों का एक गिरोह जिले में घूम रहा है। ये लोग मुख्यालय से दूरदराज के गांवों को चुनकर वहां इस काम को अंजाम दे रहे हैं। धवइझर जैसे आदिवासी बहुल पिछड़े गांवों में अधिकतर लोग कम जागरूक हैं ऐसे में ये लोग शासकीय योजनाओं का लालच देकर अवैध उगाही कर रहे हैं। करकेली जनपद में 110 ग्राम पंचायतें व 353 गांव हैं। इन गांवों में लगभग 41,517 से अधिक हितग्राही लाड़ली बहना के हैं, यदि समय पर इस सर्वे की सत्यता सामने नहीं आई तो 20 लाख 75,850 रुपए जनपद की लाड़ली बहनों को चुकाना पड़ सकता है।

करकेली सीईओ की भूमिका संदिग्ध

जानकार बताते हैं कि वर्तमान समय में पंचायतों में एक से अधिक पहचान पत्र (समग्र आइडी, आधारकार्ड व वोटर आईडी) जैसे दस्तावेजों में मकान नंबर अंकित रहता है। फिर भी जनपद सीईओ जैसे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इस तरह सभी पंचायतों को पत्र जारी करना कई सवाल खड़े करता है। जिले में यह कोई पहला मामला नहीं है इसके पहले सितंबर माह 2025 में पाली जनपद सीईओ ने भी सभी पंचायतों को इसी तरह का पत्र जारी कर मकान नंबर प्लेट को स्वैच्छिक बताकर बिहार के किसी व्यक्ति को पंचायत, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के सहयोग से घरों में लगवाने का पत्र जारी कर चुके हैं।

ग्रामीणों ने आपत्ति दर्ज कराई

ग्रामीणों ने बताया है कि 50 रुपए लेकर लाड़ली बहना हितग्राही के नाम से एक रसीद दी जा रही है। किसी वेडर, संस्था व नाम व वैद्य पंजीयन आदि कोई जानकारी नहीं दर्ज है। मात्र उन्हें भ्रमित कर हितग्राही से परिवार की गोपनीय जानकारी हासिल की जा रही है। सोमवार को कई ग्रामीणों ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई है।

इनका कहना है

मकान में नंबर प्लेट लगाने का कार्य स्वैच्छिक है, हमने पत्र में स्पष्ट लिखा है। लाड़ली बहना सर्वे के नाम पर रुपए मांग कर प्लेट लगाई जा रही है तो मैं जांच करवाकर कार्यवाही करूंगी।

हरनीत कौर कलसी, सीईओ करकेली

मैंने 100 रुपए दिए हैं, घर में एक अज्ञात व्यक्ति आया था, साथ में पंचायत सहायक थे। उन्होंने कहा था कि लाड़ली बहना का सर्वे चल रहा है। नाम जुड़वाने के नाम पर प्रति हितग्राही के हिसाब से दो लोगों के नाम पर 100 रुपए लिये हैं।

कारे लाल, निवासी धवइझर

मतदाता सत्यापन में नागरिक करें सहयोग : झा

▶ मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू

नवभारत उमरिया 4 नवंबर। उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मप्र में विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया प्रारम्भ की जा रही है। अभियान के अंतर्गत 4 नवम्बर से 4 दिसम्बर तक सभी विधानसभा क्षेत्रों में घर-घर जाकर मतदाता सूची का सत्यापन किया जाएगा।

इस अवधि में प्रत्येक बूथ लेवल अधिकारी मतदाताओं के निवास पर जाकर उनके नाम, पता, आयु एवं अन्य विवरणों का भौतिक सत्यापन करेंगे। निर्वाचन आयोग द्वारा सभी नागरिकों से इस प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी एवं पूर्ण सहयोग का आग्रह किया गया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मप्र संजीव झा ने मतदाताओं से अपील की है कि जब बीएलओ आपके घर आएँ, तो कृपया उन्हें आवश्यक सहयोग प्रदान करें। बीएलओ के पास पहले से मतदाता सूची 2025 के विवरण के अनुसार आपके नाम, पता और इपिक नंबर सहित प्री-प्रिंटेड एन्यूमरेशन फॉर्म होगा। नागरिकों से अपेक्षा की जाती है कि वे इस फॉर्म में भरी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक जांचे तथा पुष्टि करें।

बीएलओ कोई भी दस्तावेज़ एकत्र नहीं करेगा- जिन परिवारों में कोई नया सदस्य 1 जनवरी 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है. उनका नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए बीएलओ ?द्वारा फॉर्म-6 उपलब्ध कराया जाएगा। यदि किसी परिवार सदस्य का निधन हो गया हो या वह अन्यत्र स्थानांतरित हो गया हो, तो उसकी जानकारी भी बीएलओ को दें ताकि सूची से नाम विलोपित किया जा सके। उन्होंने कहा कि यह ध्यान देने योग्य है कि घर-घर सर्वेक्षण के दौरान बीएलओ कोई भी दस्तावेज़ एकत्र नहीं करेगा। दस्तावेज केवल तभी आवश्यक होंगे जब किसी प्रविष्टि का सत्यापन पूर्ववर्ती रिकॉर्ड से मेल न खाए।

सरकार त्वरित राहत राशि प्रदान करें : अजय सिंह

▶ धान की फसल बर्बाद, बेमौसम बारिश से किसानों की बढ़ी परेशानी

नवभारत उमरिया 4 नवंबर। जिले में बेमौसम बारिश का कहर इस कदर बरपा कि खेतों में कटी और खड़ी दोनों तरह की धान की फसल तबाह हो गई। ऐसे में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक अजय सिंह ने मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केन्द्र सरकार से किसानों के सामने आए इस अभूतपूर्व संकट को देखते हुए त्वरित आर्थिक राहत प्रदान करने तथा समस्त कृषि ऋण माफ करने की मांग की है।

अजय सिंह ने कहा कि जिले के किसानों ने इस बार अच्छी बारिश की उम्मीद में कर्ज लेकर धान की खेती की थी, लेकिन कटाई के दौरान ही आई भारी बारिश ने खेतों में रखी फसल को पानी में डुबोकर पूरी तरह नष्ट कर दिया। वहीं खड़ी फसल भी जलभराव के कारण झड़ गई, जिससे कई किसानों को उत्पादन लागत तक निकलने की उम्मीद नहीं है। इससे अन्नदाताओं पर कर्ज का बोझ और जीवन-यापन की समस्या गहराती जा रही है।

स्वच्छता के कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं : बागरी

▶ प्रभारी मंत्री ने की नगरीय विकास कार्यों की समीक्षा

डिंडौरी, नवभारत 4 नवंबर। सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिले की प्रभारी मंत्री एवं नगरीय विकास एवं आवास राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी की अध्यक्षता में नगर परिषद डिंडौरी एवं शहपुरा की विकास कार्यों की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई।

बैठक में उन्होंने दोनों नगर परिषदों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि नगर के बाजारों और वार्डों में किसी भी प्रकार की गंदगी न हो तथा घर-घर कचरा संग्रहण के दौरान सूखा और गीला कचरा अलग-अलग एकत्र किया जाए। उन्होंने कहा कि स्वच्छता कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

आय स्रोतों पर ठोस कदम उठाने होंगे

राजस्व वृद्धि पर जोर देते हुए मंत्री ने कहा कि 'नगर परिषदों को आय बढ़ाने के लिए नए कर, दुकानों के किराये एवं अन्य आय स्रोतों पर ठोस कदम उठाने होंगे। उन्होंने बताया कि नगर परिषद का बिजली बिल लगभग 12 लाख रुपये प्रतिमाह आता है, इसे कम करने के लिए सोलर पैनल स्थापना के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में पार्षदों द्वारा सीवर लाइन की गलत बिछाई गई पाइपलाइन से जुड़ी समस्याएं रखी गईं, जिन पर मंत्री ने संबंधित एजेंसी को 15 दिनों में निराकरण करने और कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।

पर्यटन विकास हेतु डीपीआर तैयार करें

नगरीय प्रशासन विभाग की प्रस्तुति में कई प्रस्ताव रखे गए, जिनमें झूला पुल निर्माण, चैनल फाटक, ट्रीटमेंट प्लांट, गौशाला, घर-घर कचरा संग्रहण, और पर्यटन विकास के लिए नर्मदा नदी में वाटर स्पोर्ट्स एवं नाव संचालन जैसी योजनाएं शामिल थीं। मंत्री ने कहा कि पर्यटन विकास हेतु डीपीआर तैयार कर शासन को भेजें, ताकि योजनाओं की स्वीकृति के बाद कार्य प्रारंभ किए जा सकें। उन्होंने बजट उपलब्ध कराने का आश्वासन भी दिया।

छात्रों को बताए गए स्व-सुरक्षा के उपाय

▶ ऑपरेशन मुस्कान के तहत पुलिस की जनजागरूकता की पहल

डिंडोरी, नवभारत 4 नवंबर। सुरक्षा एवं सशक्तिकरण हेतु संचालित विशेष अभियान 'ऑपरेशन मुस्कान' के अंतर्गत डिंडौरी जिले में जनजागरूकता कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की गई।

महिला सुरक्षा डीएसपी पुरुषोत्तम मरावी द्वारा कन्या परिसर स्कूल, रैपुरा में आयोजित कार्यक्रम में लगभग 300 छात्र-छात्राओं एवं स्कूल स्टाफ को बाल अधिकार, सुरक्षा एवं आत्मसुरक्षा से संबंधित जानकारी दी गई।अभियान के तहत थाना करंजिया द्वारा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, उमरिया में छात्रों को ऑपरेशन मुस्कान के उद्देश्य, बच्चों की सुरक्षा, अधिकारों की जानकारी एवं स्व-सुरक्षा के उपाय बताए गए।

अनजान लोगों की बातों में नहीं आएं-इसी क्रम में थाना बजाग क्षेत्र के ग्राम धुरकुटा एवं चांडा, थाना मेहंदवानी के ग्राम परापानी तथा थाना समनापुर के कन्या शाला, समनापुर में भी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसके तहत संदेश दिया गया कि अज्ञात व्यक्तियों से सतर्क रहें, अनजान लोगों की बातों में नहीं आएं। सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें; किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना अभिभावक या पुलिस को दें। हर बालक-बालिका को शिक्षा, सुरक्षा और समान अवसर का अधिकार है। किसी बच्चे के लापता होने पर तुरंत पुलिस को सूचित करें।